घाटे में चल रही औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बन्द करने के संबंध में आठवीं योजना के लिए प्रारूप-पत्र

1792. **श्री जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार किए गए अपने प्रारूप-पत्र में सरकार को सलाह दी है कि जो औद्योगिक इकाइयां, आर्थिक प्रबंधात्मक तथा तकनीकी तौर पर पुनर्गठित किए जाने के बाद भी घाटे में चल रही हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रारूप पत्र पर गम्भीरता से विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात देश में सार्वजनिक क्षेत्र की कुल कितनी औद्योगिक इकाइयों को बंद किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं । आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अभी तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

भू-वैज्ञानिक और खनन निदेशालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश के कार्यालय से भारत-चीन सीमाओं के नक्शों का गुम होना

1793. **श्री सोहन लाल धूसिया :**
श्री अजीत जोगी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भू-वैज्ञानिक और खनन निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से भारत-चीन सीमा के क्षेत्रों से संबंधित करीब एक सौ नक्शे गायब पाए गए हैं ;

(ख) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस मामले में कितने कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है तथा क्या उनमें से किसी कर्मचारी को निलंबित भी किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। भू-वैज्ञानिकों और खनन निदेशालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, सरकार ने बताया है कि उनके कार्यालय से भारत-चीन सीमा क्षेत्र से संबंधित कोई नक्शा गायब नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Growth of Gross Domestic Products

1794. SHRI KAMAL MORARKA:
SHRI YASHWANT SINHA:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state what is the percentage shift of employment *inter-se* between agriculture industry and services sector, respectively for the 7th Five Year Plan period, as compared to 1st Five Year Plan period?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): The only comparable estimates of sectoral distribution of workers over a long period of time are available from the Census. A statement giving the percentage distribution of workers by Agriculture, Industry and Services

based on the 1951 and 1981 Census is enclosed.

Statement

Percentage distribution of Workers, Census 1951 and 1981-All India.

	Industry Group	1951	1981
I.	Agriculture & Allied (including Cultivators, Agricultural Labourers Allied activities like plantation etc.)	72.1	68.7
II.	Industry (including Mining & Quarrying, Manufacturing & Construction)	10.7	13.5
III.	Services (including Trade & Commerce, Transport, Storage & Communication and other Services)	17.2	17.8

1795. [*Transferred to the 4th May, 1989*]

Promotion of Special List Commissioned officers in Army

1796. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI DEBA PRASAD RAY:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a provision has been made for promotion of Special List Commissioned Officers in the Army as Lt. Colonels on Time-scale basis, while similar provision has not been made in respect of equivalent rank officers in the Navy;

(b) if so, what are the reasons for the disparity between Army and Naval Officers; and

(c) what steps are being taken to bring about a parity between the officers of the two wings?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) to (c) In the Army, Special List Commissioned Officers of the rank of Major, who do not make the grade for Lt. Col. (Selection), are subject to certain conditions, eligible for promotion to the rank of Lt. Col. (time-scale) on completion of 21 years commissioned service. They do not get the rank pay of a Lt. Col. and they continue to be reckoned against the authorised streng h of Majors.

In the Navy there is no provision for a time-scale promotion for Lt. Cdr. (Special Duty List) to the rank of a Commander. A Lt. Commander (Special Duty List) is, however, eligible to be considered for promotion to the rank of a Commander in the General list on the basis of merit. The two categories are disparate and do not call for any parity.

Wrongful award of Kshanika Oration Award to a Professor of PGIMER, Chandigarh

1797. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI DEBA PRASAD RAY:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news which appeared in the Patriot of April, 13, 1989 under the caption 'An Award of contention' to the effect that Dr. Saroj Mehta, Professor PGIMER, Chandigarh, had been wrongfully awarded the ICMR Kshanika Oration